आयुष्मान का पाखंड बनाम ईएसआई की हकीकत

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की इच्छा न तो कभी कांग्रेस सरकार की रही थी और न ही कभी मोदी सरकार की। लेकिन इसके नाम पर जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिये दोनों ने ही एक से बढ़कर एक पाखंड को जन्म दिया।

चिकित्सा सेवाओं के नाम पर जहां कांग्रेस ने आरएसबीवाई (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) का धंधा शुरू किया था तो वहीं मोदी ने 'आयुष्मान' योजना के द्वारा जनता को ठगने की योजना बना डाली। आरएसबीवाई में जहां 30 हजार रुपये तक के इलाज की बात कही गई थी वहीं मोदी ने आयुष्मान में पांच लाख तक के मुफ्त इलाज का डंका बजा रखा है। सन् 2018 में शुरू की गई इस योजना के द्वारा देश के 50 करोड़ गरीब लोगों को चिकित्सा लाभ देने का ढोल पीटते हुए इसे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा बताया गया था।

50 करोड़ लोगों को आयुष्मान सेवा का ढोल तो पीट दिया लेकिन बीते छः साल में अभी तक इसके आधे यानी 25 करोड़ लोगों को ही कार्ड जारी हो सके हैं। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार केवल 25 हजार प्रति दिन के हिसाब से कार्ड बनाये जा रहे हैं। इस हिसाब से 100 दिन में 25 लाख और 400 दिन में एक करोड़। अब सुधी पाठक बाकी हिसाब खुद ही लगा लें कि 50 करोड़ का दावा यह सरकार कितने वर्षों में पूरा कर पाएगी?

दूसरी गौरतलब बात यह है कि इस योजना में कुल खर्च का 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकारों से वसूला जाता है। दिल्ली तथा कई अन्य गैर भाजपाई सरकारों ने इस योजना को सिरे से नकार दिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कहना है कि जब वे प्रत्येक मरीज़ को मुफ्त एवं बेहतरीन चिकित्सा सेवा दे रहे हैं तो मोदी नाम का ढिंढोरा पीटने के लिये वे काहे को अपना धन बर्बाद करें?

इसके प्रचार-प्रसार एवं कार्ड बनाने पर ही लाखों-करोड़ खर्च किये जा चुकने के बावजूद अभी तक मात्र 25 करोड़ लोगों को ही इस योजना से जोड़ा जा सका है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन पंजीकृत कार्डधारकों में से अभी तक केवल साढ़े पांच करोड़ लोग ही किसी प्रकार की चिकित्सा सेवा इस योजना के तहत प्राप्त कर सके हैं। ये आंकड़े कितने खोखले एवं धोखाधड़ी से भरपूर हैं इसका अनुमान कैग की ताजा तरीन रिपोर्ट से लगाया जा सकता है।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ही मोबाइल नम्बर से सैंकड़ों आयुष्मान कार्ड बनाकर बड़ा फ़र्जीवाड़ा किया गया है। बात यहीं खत्म नहीं होती ऐसे सैंकड़ों मृत लोगों की सूची भी कैग ने जारी की है जिनका 'इलाज' एक से अधिक अस्पतालों में करके सैंकड़ों करोड़ डकार लिये गये।

दरअसल समझने वाली बात तो यह है कि जनता को चिकित्सा सेवाएं केवल डॉक्टरों एवं संसाधनों से सुसज्जित अस्पतालों द्वारा ही दी जा सकती है न कि किसी बीमा कम्पनी एवं इसकी योजनाओं द्वारा। उक्त दोनों ही सरकारों ने डॉक्टरों एवं अस्पतालों की पुख्ता व्यवस्था करने की बजाय बीमा योजनाओं का छलावा देकर जहां एक ओर जनता को बेवकूफ़ बनाया है वहीं दूसरी ओर धोखाधड़ी करने में माहिर लोगों के लिये लूटने खाने के सुअवसर प्रदान करा दिये हैं।

आयुष्मान योजना के तहत इलाज के करीब 1400 पैकेज तैयार किये गये हैं। इनमें से आधे पैकेज सरकारी अस्पतालों तथा शेष प्राइवेट अस्पतालों के लिये रखे गए हैं। गौरतलब है कि देश के तमाम सरकारी अस्पतालों की हालत फ़रीदाबाद के बीके अस्पताल से भी गई बीती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि यहां किसी का भी इलाज कैसा हो पाएगा? पर फिर यदि बीके जैसे सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराना है तो आयुष्मान कार्ड की क्या भूमिका हो सकती है? संदर्भवश इस योजना में प्राथमिक श्रेणी के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि जो इलाज बिना अस्पताल में दाखिल हुए हो सकता है वह इसमें कवर नहीं होता, अर्थात केवल दाखिल होने वाले रोगी ही इसके दायरे में आते हैं।

अब आ जाइये ईएसआईसी की चिकित्सा सेवाओं की ओर। आज के दिन करीब 16 करोड़ लोग ईएसआईसी से चिकित्सा सेवाएं लेने के हकदार हैं। चौंकिये नहीं एक बीमाकृत व्यक्ति के साथ चार लोगों का परिवार माना जाता है। आज के दिन इन बीमाकृतों की संख्या पौने चार करोड़ है तो कुल 15 करोड़ लोग इस सेवा के हकदार हो जाते हैं। इतना ही नहीं सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी कि जिनका अंशदान कार्पोरेशन को नहीं आता और केवल 120 रुपये वार्षिक देकर ईएसआई से जुड़े रहते हैं, उनको मिला कर यह संख्या 16 करोड़ के आसपास बनती है।

अब देखने वाली विशेष बात यह है कि अभी तक आयुष्मान में पंजीकृत हुए 25 करोड़ लोगों में से बीते छः साल में जहां केवल साढ़े पांच करोड़ लोगों ने ही चिकित्सा सेवाएं प्राप्त की हैं वहीं ईएसआईसी में पंजीकृत 16 करोड़ लोगों में से तीन-साढ़े तीन करोड़ लोग हर वर्ष चिकित्सा सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि ईएसआईसी की सेवाओं में भी अनेकों खामियां है, इसके बावजूद भी इसकी सेवाओं के सामने आयुष्मान की सेवाएं कहीं नहीं ठहर पातीं।

मजे की बात तो यह है कि ईएसआई सेवाओं पर सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं होता क्योंकि सारा पैसा मज़दूरों के वेतन से वसूला जाता है। केवल राज्य सरकारों से 12.33 प्रतिशत उन सेवाओं के लिये लिया जाता है जिन्हें राज्य सरकारें चलाती हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित ऐसी ईएसआई सेवाओं की बदहाली से त्रस्त मज़दूर उन्हें लेने से भी कतराते हैं। जबकि आयुष्मान की ड्रामेबाजी पर सरकार लाखों-करोड़ रुपये बर्बाद कर चुकी है और करती ही जा रही है।

रोबोटिक सर्जरी उपकरण के लिये ईएसआईसी ने जारी किया 25 करोड़ का टेंडर

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) सभी प्रकार की महीन सर्जरी में अति उपयोगी सिद्ध हो रहे रोबोटिक उपकरण प्राप्त करने के लिये, एनएच तीन स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने बीते सप्ताह इस उपकरण को खरीदने के लिये टेंडर जारी कर दिया है। अमेरिका से आयात होने वाला यह उपकरण देश भर में शायद पहला ही हो। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली स्थित एम्स में भी इस दर्जे का उपकरण अभी तक नहीं लगा है।

25 करोड़ के इस उपकरण को सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) के तहत नेशनल पॉवर ग्रिड लगवा रहा है। इस बाबत ग्रिड अधिकारियों तथा ईएसआई कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के बीच इसी माह के शुरू में करारनामे पर हस्ताक्षर हो गये थे। इस उपकरण की खूबियों के बारे में 'मज़दूर मोर्चा' पहले भी विस्तार से लिख चुका है। किसी भी सर्जरी के दौरान जहां सर्जन की नजर एवं उसके औजार आसानी से नहीं पहुंच सकते वहां इस उपकरण के द्वारा सर्जरी को कहीं और बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। इसके अलावा इस उपकरण के द्वारा अमेरिका या इंग्लैंड में बैठा सर्जन भी बेहतर सर्जरी को अंजाम दे सकता है।

सीएसआर द्वारा इस अस्पताल को मिलने वाला ये कोई पहला उपकरण एवं अनुदान नही है। इससे पहले भी इंडियन ऑयल व कई अन्य संस्थानों व एनजीओ आदि ने यहां अपना योगदान दिया है। इस तरह के जन सहयोग के पीछे केवल यहां कार्यरत फैकल्टी एवं स्टाफ़ की कार्य कुशलता मेहनत एवं लगन से प्रभावित होकर ही विभिन्न प्रतिष्ठान सहयोग के लिये अपना हाथ बढ़ा रहे हैं।

बिल्डर-भू माफिया के पक्ष में ही बोलते हैं खट्टर

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) बिल्डरों-भू माफिया के चहेते मुख्यमंत्री खट्टर अपने इन खास लोगों के हित में काम करने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने इन माफिया के गलत निर्माणों को वैध करने के लिए भवन निर्माण पॉलिसी में भी बदलाव करने की घोषणा की है। रविवार को अंबाला में आयोजित जन सुनवाई बैठक के दौरान खट्टर ने घोषणा की कि आवासीय क्षेत्र में बने व्यावसायिक भवन, प्रतिष्ठान और शोरूम को अनुमति देने के लिए सरकार नई नीति पर काम कर रही है। यानी खट्टर अब प्रदेश भर में अपने उन चहेते बिल्डर, विधायक, उनके रिश्तेदारों, पार्टी कार्यकर्ताओं के नियम विरुद्ध और अवैध ढंग से बनाए गए अरबों रुपये कीमत के निर्माण को वैध कर उन्हें उपकृत करेंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सहूलियत पहले से ही व्यावसायिक भवनों में तब्दील हो चुके आवासीय क्षेत्रों को ही मिलेगी नए आवासीय क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुराने भवनों के लिए पॉलिसी बना कर उन इलाकों को व्यावयायिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा।

खट्टर ने यह घोषणा कर उन लोगों को मायूस किया है जो नियम कानून का पालन करते हैं और उन लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं जो नियम विरुद्ध निर्माण कर मोटा पैसा कमा रहे हैं। बड़खल विधायक सीमा त्रिखा भी सरकार का अंग हैं बहुत संभव है कि खट्टर की भविष्य में बनने वाली इस पॉलिसी की उन्हें पहले से ही जानकारी हो इसीलिए उनके देवर ने एनआईटी तीन ए ब्लॉक के आवासीय परिसर को व्यावसायिक भवन में तब्दील कर उसमें बाकायदा किराए पर खाली है का बोर्ड भी टांग दिया। सरकार बनने के बाद से ही खट्टर सरकार पर बिल्डर और भू माफिया के पक्ष में काम करने के आरोप लगते रहे हैं। अब चुनावी वर्ष शुरू हो गया है और राजनीतिक पार्टियों

को फाइनेंसरों की जरूरत है, ऐसे में खट्टर ने यह घोषणा करके अपने फाइनेंसरों को खुश कर दिया है।

हालांकि खट्टर ने कहा कि यह पॉलिसी केवल पुराने भवनों पर ही लागू होगी, नए भवन नहीं बनने दिए जाएंगे। प्रशासनिक अमले से लेकर राजनेताओं में लुंज पुंज नेता की पहचान रखने वाले खट्टर की इस बात को बिल्डर और भू माफिया शायद ही कोई भाव देंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुख्यमंत्री ऐसे नियम विरुद्ध निर्माणों को वैध कराने के लिए फिर से नई पॉलिसी लाने की घोषणा कर देंगे। खट्टर भी अन्य राजनेताओं की तरह इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि सत्ता एक दिन जानी ही होती है, ऐसे में अपना और अपने चहेतों का जितना भला हो सकता है कर लिया जाए।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।